जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 170 प्रभात अजमेर, बुधवार 19 जनवरी, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ टाइगर शार्क उत्तर में और आगे तक जा रही हैं। एटलांटिक ओशन में इन परभक्षी जीवों का मूवमैंट ईकोसिस्टम को गड़बड़ा सकता है तथा मरीन प्रोटैक्टेड क्षेत्र के बाहर जाना इन शार्क के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के पास समुद्र का पानी विश्व के अन्य स्थानों की तुलना में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। मनुष्य जनित जलवायु परिवर्तन के कारण एटलांटिक महासागर के इस भाग का तापमान 1980 के दशक के बाद से 2.7 डिग्री फैरनहाइट बढ़ गया है। तेजी से हुए इन अति गंभीर परिवर्तनों ने मरीन इकोसिस्टम को बदला है, कुछ प्रजातियाँ नए क्षेत्रों की तरफ चली गई हैं और कुछ अपने मूल आवासों से बिल्कुल गायब हो गई हैं। उदाहरण के लिए, ठण्डा पानी पसंद करने वाली एटलांटिक कॉड मछली के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 60 से 80 वर्षों में ये न्यू इंगलैंण्ड के तट के पास से लगभग गायब ही हो जाएंगी और यह परिवर्तन मछली पकड़ने के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के प्रयास को गंभीर रुप से जटिल बना देगा। ज्ञातव्य है कि 1992 में यह व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गया था। गत दिनों ''ग्लोबल चेंज बायॉलजी'' में प्रकाशित एक नए शोध में बताया गया है कि यह तीव्र गर्माहट इस क्षेत्र के शीर्ष परभक्षी, टाइगर शार्क के माइग्रेशन को परिवर्तित कर रही है। ये शार्क, जो पन्द्रह फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं और सी टर्टल से लेकर लॉबस्टर तथा कार के पार्ट्स तक, सब कुछ खा लेती हैं, गर्मी के मौसम में उत्तर की तरफ लगभग 270 मील दूर और आगे तक जा रही हैं और 1980 के दशक के मुकाबले एक महीने पहले यहाँ पहुँच रही हैं। इन शार्क का बदलता हुआ माइग्रेटरी पैटर्न पानी के तापमान में बदलाव से पूरी तरह मैच करता है।

आप के लिये पंजाब में बहुमत पाने का मौका 2017 में था

तब लगातार दस साल सत्ता में रहने के कारण अकाली-भाजपा के खिलाफ ''एन्टी इनकम्बैंसी'' का माहौल था

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जनवरी। आम आदमी पार्टी (आप) ने संगरूर के सांसद भगवंत सिंह मान को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है इससे यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी इतनी बढ़त बना लेगी कि राज्य में सरकार बना सके?

टाइम्स नाओ-नवभारत-वीटो द्वारा आयोजित एक हालिया सर्वे के अनुसार पंजाब त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है जिसमें बताया गया कि आप को सब से ज्यादा 40.32 प्रतिशत वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 34.8 प्रतिशत अकाली दल-बसपा गठबंधन को 16.8 प्रतिशत। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 44-45 सीटें जीत सकती है और आप 55-58 सीटें जीत सकती है।

राजस्थान, हिमाचल और केरल की तरह पंजाब में भी चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। सन् 2012 में अवश्य यह प्रवृत्ति बदली थी जब अकाली दल पूरे दस साल सत्ता में रहा था।

- **वोटर, एक बार कांग्रेस उसके बाद अकाली गठबंधन की सरकार की अदला-बदली से भी ऊब गए, इस ऊब का लाभ 2017 में आप को मिला। आप का वोट शेयर व सीटें काफी बढ़ीं, पर आप बहुमत नहीं पा सकी थी।**
- **इस बार परम्परा अनुसार कांग्रेस की सरकार की हारने की बारी है, पर अकाली काफी कमजोर हैं, कांग्रेस को हराकर सत्ता पाने के लिये, इसका लाभ आप को मिलना स्वाभाविक ही है, पर आप की संगठनात्मक कमजोरी व पूरे पंजाब में विस्तार न होना, उसका यह मौका भी फलीभूत होने से रोक सकता है।**
- **इससे भी बड़ा, आप को सत्ता में आने से रोकने का कारण यह है कि, यह कांग्रेस के ''एन्टी इनकम्बैंसी'' माहौल को बांटने के लिये, कई अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में, जैसे कैप्टन अमरिन्दर सिंह-भाजपा गठबंधन, किसानों की ओर से धरना व आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के दो धड़ों द्वारा बनायी गयी दो पार्टियां, जो पंजाब में चुनाव में उतरी हैं।**

सन् 2017 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में सर्वश्रेष्ठ मौका था तब यद्यपि पार्टी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई थी पर इस बार संकेत मिल रहे हैं कि पंजाबी मतदाता शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की दो दलों वाली राजनीति से उकता गया है। चुनाव विश्लेषकों की नजर में तो आप पहले नम्बर की पार्टी बन गई है पर पंजाब में इसकी मुहिम आसान नहीं होगी और इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि इस बार कई पार्टियां मैदान में हैं। इनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस तथा किसानों की पार्टियां भी शामिल हैं जिनमें बलबीर सिंह राजेवाल की संयुक्त समाज मोर्चा, गुरनाम सिंह की संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख है। इसीलिए बहुकोणीय मुकाबले में सरकार विरोधी वोट बंटने की भारी संभावना है। दूसरा कारण यह है कि जहां अरविंद केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी का दर्जा बढ़ रहा है पर पार्टी के पास ना तो पूरी तैयारी है ना ही कार्यकर्ता। कई जगहों पर तो पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं है जैसे देओबा और माझा क्षेत्र। और राज्य की कुल 118 सीटों में से 48 इसी क्षेत्र की हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पारसी समुदाय दुविधा में है, अपने मुर्दों का निस्तारण कैसे करें

समुदाय की परम्परागत रीतियों के अनुसार मृतक को वस्त्रहीन अवस्था में ''टावर ऑफ साइलैंस'' में रखा जाता है, गिद्धों के भक्षण हेतु

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया है कि वे ज्यूरिस्ट फली एस. नरीमन और केन्द्रीय अधिकारियों के साथ बैठें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल में संशोधन करे ताकि पारसी समुदाय जोरोसिट्रयन परम्परा के अनुसार कोविड संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें।

तुषार मेहता इस मामले में केन्द्र की तरफ से मौजूद हैं तथा नरीमन, जो स्वयं पारसी हैं, सूरत पारसी पंचायत बोर्ड की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। उक्त बोर्ड ने कोविड से मरने वाले पारसी लोगों के (टावर ऑफ साइलैंस) की परम्परा के अनुसार अंतिम संस्कार के अधिकार की रक्षा करने की मांग की है। इस धर्म में दाह संस्कार का निषेध है जैसा कि इस महामारी में प्रशासन का निर्देश है।

दस जनवरी को भेजे गए नोटिस के तहत जारी हलफनामे में केन्द्र ने कहा है

- **पारसियों की मान्यताओं के अनुसार अग्नि सबसे शुद्ध शक्ति है, जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता, शवों को उसमें जला कर।**
- **पर अभी कोविड महामारी के कारण शव को निर्वस्त्र नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मृत्यु के नौ दिन बाद तक शव से कई लिक्विड बहते हैं, जो संक्रमित हो सकते हैं।**
- **यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत है तथा वरिष्ठ एडवोकेट फली नरीमन, जो स्वयं पारसी हैं, पारसी समुदाय की ओर से पैरवी कर रहे हैं।**

प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार या दफनाए जाने की ही अनुमति दी गई है।

जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ एवं सूर्यकांत की बैंच ने सोमवार को दूसरी सुनवाई में इस मसले के हल के लिए अनौपचारिक बैठक की जाए। बैंच ने केन्द्र सरकार से कहा है कि यह पता लगाए कि प्रोटोकॉल में किस हद तक बदलाव किया जाए ताकि धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि वैज्ञानिक रूप से यह संभव नहीं है।

शपथ पत्र कहता है कि इन निर्देशों का मूल यह है कि मृत शरीर पूरी तरह से ढका हुआ होगा ताकि उससे डील कर रहे लोग उसके प्रत्यक्ष संपर्क में ना आएं, इन लोगों में परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं और नहीं भी। इन लोगों का मृत शरीर से संबंधित किसी भी तरह का स्राव से स्पर्श नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रमाण जो अभी तक मिल हैं उनसे पता चला है कि ''करोना वायरस मृत शरीर पर शरीर के तरल, स्राव, नम कोशिकाओं में 9 दिन तक जीवित रह सकता है।''

शपथ पत्र कहता है कि ''इन चिंताओं को देखते हुए कोविड मरीज के मृत शरीर के दाह संस्कार या दफनाए गए बगैर खुला छोड़कर अंतिम संस्कार की अनुमति देना उचित नहीं है।''

नरीमन ने कहा कि ''हम मृत शरीर के अंतिम संस्कार में केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गरिमा बनाए रखने के पक्ष में हैं।''

उन्होंने कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य शव को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पारसियों के पेशेवर लोग होते हैं जो शव को ले जाते है तथा शव को टावर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जे.एन.यू. छात्रा से छेड़छाड़ का मामला दर्ज

नई दिल्ली, 18 जनवरी (वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जे.एन.यू.) की पी.एच.डी. की छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी परिसर में छेड़छाड़ के

- **छात्रा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि, सोमवार की रात करीब पौने बारह बजे जब वह टहल रही थी तभी कैम्पस परिसर में मोटरसाइकिल पर आये युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर युवक भाग गया।**

प्रयास के बाद मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने बताया कि उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से छेड़छाड़ के संबंध में फोन आया था। पुलिस ने बताया कि छात्रा सोमवार की रात करीब पौने बारह बजे युनिवर्सिटी के ईस्ट गेट रोड पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रहरी बंदी के लिये अफीम का दूध लाया, बाहर की थड़ी से

जोधपुर, 18 जनवरी (कासं)। जोधपुर केन्द्रीय कारागार एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां तैनात एक आर.ए.सी. कर्मी के जूतों में से अफीम के दूध से भरी पोलिथीन थैलियां बरामद की गई हैं। वैसे जेल में समय समय पर चलने वाली आकस्मिक जांच में कई बार अवांछिय साम्रगी पकड़ी जाती रही है। यह साम्रगियां खुद जेल के कार्मिक पहुंचाते है या नहीं इसका आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया। लेकिन सोमवार को एक जेल प्रहरी के दोनों जूतों में रखी अफीम के दूध से भरी थैलियां बरामद होने के साथ ही इसका एक ठोस सबूत मिल गया। दूध की मात्रा 95 ग्राम बतायी गई है। अफीम का दूध वह एक बंदी के कहे अनुसार जेल परिसर के नजदीक बनी होटल पर लेने गया था। पुलिस ने जेल प्रहरी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ की है।

रातानाडा थाने के सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह ने बताया कि केंद्रीय कारागार के आरएसी 13 वीं बटालियन के कंपनी प्लॉटून कल्याणसिंह की तरफ से इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है। इनके अनुसार वह सोमवार को अपनी ड्यूटी पर थे, तब आसोप के दाड़मी

- **जोधपुर के सैन्ट्रल जेल में हालात काफी हास्यास्पद।**

गांव का रहने वाला जेल प्रहरी प्रहलाद पुत्र उर्जाराम देवासी सुबह अपनी ड्यूटी पर आया और उसी दौरान जेल में आरएसी की तरफ से चैकिंग की गई। प्रहलाद के संदिग्ध लगने पर उसके सर्विस जूते उतरवाए गए। इस पर जूतों में से दो अलग अलग पॉलिथिन थैलियों में 95 ग्राम अफीम का दूध मिला। इस पर उसे पकड़ कर रातानाडा पुलिस के हवाले किया गया।

एसआई भंवरसिंह ने बताया कि आरोपी जेल प्रहरी प्रहलाद देवासी से आरंभिक पूछताछ में पता लगा कि वह यह अफीम का दूध जेल में एक बंदी के कहे अनुसार बाहर होटल से लाया था। होटल पर बंदी का परिचित मिला और उसने यह अफीम का दूध दिया था।

उन्होंने बताया कि बंदी को नामजद किया गया है। फिलहाल प्रहरी की बातों की तस्दीक की जा रही है। अफीम मंगवाने वाला बंदी कोई तस्कर या हार्डकोर अपराधी भी हो सकता है। प्रहलाद को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड पर लिया जाएगा।

जेल से बंदी के कॉल करने का भी संदेह गहराया:

इन दिनों कोविड के चलते जेल में बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात आदि की मनाही है। अब संदेह गहरा रहा है कि जेल कार्मिकों की मिली भगत से बंदी को उसके परिचित से बातचीत करवाई होगी। तब परिचित ने अफीम का दूध होटल पर भिजवाया होगा और प्रहरी उसे ही लेने वहां गया होगा।

कम्युनिटी किचन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जनवरी। देश में भूख से हुई किसी मौत के बारें में ना बताने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्र सरकार की खिंचाई की और उससे कहा कि वह भूख और कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए एक मॉडल स्कीम तैयार करें ताकि वे सामुदायिक रसोईयों का संचालन कर सकें।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हीमा कोहली की एक बैंच ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से कहा कि

- **सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर, सरकारों को भुखमरी से होने वाली मौत रोकने के लिये ''कम्युनिटी किचन'' चलाने पर जोर दिया।**

''भारत सरकार को भूख से हुई मौतों के नवीनतम आंकड़े हमें उपलब्ध करवाने चाहिए। आप अपने अधिकारी से कहें कि वह हमें यह जानकारी उपलब्ध करवाएं।''

बैंच ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए कि वे कुपोषण, भूख से हुई मौतों व अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित आंकड़े दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाएं।

अटॉर्नी जनरल ने देशभर में सामुदायिक रसोईयों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार के पास फण्ड्स की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि केन्द्र पहले ही 131 कल्याणकारी योजनाओं की फण्डिंग कर रहा है तथा राज्य सरकारों को इस स्कीम के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विन्टर ओलम्पिक्स

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जनवरी। चीन ने चार फरवरी से शुरु हो रहे विंटर ओलम्पिक्स देखने आने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि अधिकांश चीनी दर्शक भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि करोनावायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीजिंग 2022 की

- **चीन ने इस आयोजन के लिए जनता को टिकट न बांटने का निर्णय लिया।**

आयोजन समिति ने घोषणा की है कि यह सार्वजनिक टिकटों की बिक्री बंद कर रही है ताकि खिलाड़ियों व दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।''

यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दो दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने बीजिंग में ओमक्रॉन का पहला केस मिलने की जानकारी दी थी और उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा दिया गया तथा बीजिंग और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टैस्टिंग की जा रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक साल में राष्ट्रपति बाइडन व अमेरिकी जनता का हनीमून खत्म हुआ

नवीनतम सर्वे, 12 से 14 जनवरी के बीच करवाये गये सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति से संतुष्ट लोगों की संख्या केवल 44 प्रतिशत ही है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जनवरी। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अपना पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ही मूल विषय से भटक गए हैं? यदि सी.बी.एस. न्यूज/यू. गव. पोल के नए सर्वेक्षण पर गौर किया जाए तो इसका उत्तर ''हाँ'' में हैं।

सर्वे से पता चला चलता है कि अधिकांश अमेरिकी ऐसा मानते हैं कि बाइडन सरकार ने अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और 50 प्रतिशत प्रतिभागियों का यह कहना है कि नए राष्ट्रपति के प्रथम वर्ष के कार्यकाल ने ही उन्हें ''कुंठाग्रस्त'' कर दिया है। गत 12 से 14 जनवरी तक हुए इस सर्वेक्षण में 2 हजार 94 वयस्कों ने भाग लिया।

''ध्यान केन्द्रित करना'' एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थायी रहती है। लेकिन अधिकांश प्रतिभागियों का कहना है कि बाइडन ना तो अर्थव्यवस्था पर और ना

- **पिछले छः राष्ट्रपतियों, जिनमें डॉनल्ड ट्रम्प शामिल नहीं हैं, को उनके शासन काल के प्रथम वर्ष में इतनी कम रेटिंग नहीं मिली है।**
- **50 प्रतिशत जनता महसूस करती है कि, वह राष्ट्रपति के कामकाज से कुण्ठित है, 49 प्रतिशत लोग उनके कामकाज से निराश हैं, 40 प्रतिशत जनता उनके कामकाज से चिंतित (नर्वस) है।**
- **जनता की इन ''नैगेटिव भावनाओं'' का कारण है, जनता का मानना है कि राष्ट्रपति का फोकस महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं है, वे महत्वहीन मुद्दों पर ऊर्जा व समय बर्बाद कर रहे हैं।**
- **जनता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैंः इकॉनमी व महंगाई।**

ही महंगाई पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, जबकि केवल कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं कि बाइडन और उनके साथी डैमोक्रेट्स का ध्यान कुल मिलाकर सही विषयों पर केन्द्रित है। यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी के भीतर महंगाई ही वह विषय है जिसमें उनके साथी डैमोक्रेट्स उन्हें अन्य विषयों की तुलना में सबसे कम अंक देते हैं।

58 प्रतिशत का कहना है कि बाइडन का वाइट हाउस अर्थव्यवस्था पर उचित ध्यान नहीं दे रहा है जबकि उनकी सरकार के महंगाई प्रबंधन को लेकर 65 प्रतिशत भी ऐसी ही राय रखते हैं।

जब यह पूछा गया कि बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल में आप कैसा महसूस करते हैं? तो 50 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा ''हताश'' और 49 प्रतिशत ने इसे ''निराशाजनक'' तथा 40 प्रतिशत ने ''बेचैन'' बताया, जबकि 25 प्रतिशत ने ही इसे ''शांत'' और ''संतुष्ट करार दिया।

एक वर्ष में उनकी उन्हें पसंद करने वोल लोग मात्र 44 प्रतिशत ही रह गए हैं और अगस्त 2021 से यह 40 प्रतिशत के आसपास रही है। कार्यकाल की शुरूआत में उनकी रेटिंग 60 प्रतिशत से ऊपर थी और इसका कारण यह आशावाद था कि वे वैश्विक महामारी को नियंत्रित कर रहे हैं, हालांकि यह आशावाद अगली गर्मियों तक फीका पड़ गया।

राष्ट्रपति कार्यकाल के प्रथम वर्ष में जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वह उनके छह पूर्ववर्तियों की तुलना में कम हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प एक अपवाद है जिन्हें वर्ष 2018 में 37 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया।

लेकिन 55 प्रतिशत अमेरीकियों का कहना है कि बाइडन अपने आप को जिस तरीके से संभाल रहे हैं, वे उसे पसंद करते हैं, जबकि 62 प्रतिशत उनके आर्थिक प्रबंधन को लेकर नाखुश हैं, और 70 प्रतिशत का कहना है कि महंगाई के प्रबंधन के उनके तरीके को वे नापसंद करते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)